THE DEPUTY CHAIRMAN: There were no objections. There were certain clarifications sought from the State Government.

SHRI KALPNATH RAI: These were highly technical objections...

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI P. SHIV SHANKER):.. .which you will not understand, *(interruptions).*

SHRI KALPNATH RAI: This project will be completed within the time schedule because it is the State Government which has to complete this project and they will get it completed within the time schedule.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. T. R. Balu, absent.

श्री वीर चन्द्र प्रताप सिंह : माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं कि जब राज्य सरकार ने उत्तर नहीं दिया, फिर भी यह मामला ज्वाइंट सैक्टर में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के मिल कर बनाने में जो टाइम ओवर रन और कास्ट ओवर रन का मामला है उस जंजाल और प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो यह ज्वाइंट सैक्टर बनाने में क्या हर्ज है?

श्री कल्पनाथ राय : यह नीति सरकार के विचाराधीन है । अभी इस पर सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है इसलिए उसको एक्सैप्ट नहीं किया ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Question No. 348.

Ban on Imports of PTFE

*348. DR. BAPU KALDATE: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government propose to ban imports of Polytetra-ftuoroethylene (PTFE) a raw materials for engineering plastics;

(b> if so, what are the reasons therefor;

(c) what other arrangements have been made to need the domestic demands of PTFE;

(d) whether Hindustan Fluoro Cartons Limited has been manufacturing PTFE; and

(e) if so, whether its product has keen at per with' the imported PTFE?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI J. VENGAL RAO): (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

(d) Yes, Sir.

(e) Yes, Sir. The quality has been generally upto the mark except for some variation during the initial stages of manufacture.

डा बापू कालदाते : उपसभापति जी, यह जो पी० टी० एफ० ई० है यह एक बहुत महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग प्लास्टिक है और इसका उपयोग कई क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे—इलेक्ट्रोनिक्स, टेलिकम्युनिकेशन, रक्षा के विभाग विषय में भी है, न्यूक्लियर रिसर्च में है । यहां अपने देश में सिर्फ 200 टन तक ही इसकी डिमांड है । यह बात सही है कि सरकार ने हैदराबाद के पास एक पब्लिक अंडरटेकिंग पी० टी० एफ० ई० तैयार करने के लिए लगाया है, लेकिन वह 1987 की बात है। सवाल यह है कि आपने बैन नहीं किया, यह बात सही है, लेकिन क्या यह बात सही नहीं है कि सरकार ने उसकी जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वह 174 से 224 कर 85 परसेंट बढ़ा दी है । महोदया, आज जो अपना प्रोडक्शन है, सरकारी प्रोडक्शन है, मैं इसका स्वागत करता हूं । अगर सरकारी उद्यम बढ़ित होते हैं तो हमें तो खुशी होगी कि बजाए प्राइवेट इजेक्शन करने के हम खुद पैदा करें । लेकिन जो भी कीमत लगाया जाती है, जो बाहर से आती है पी० टी० एफ ई० उसका दाम 415 से 510 तक होता है और भारतीय प्रोडयूस का दाम 355 से लेकर 470 तक होता है। तो एक तरफ से तो इम्पोर्ट ड्यटी बढ़ा दी और दूसरी तरफ से बाहर से आने वाले पी० टी० एफ ई० का दाम भी ज्यादा है ।

इसका मतलब साफ है कि हिंदुस्तान में जो प्रोड्यूस होता है वही लोग खरीदते रहेंगे। अगर यह बात सही है तो इम्पोर्ट के लिए जो रिस्ट्रक्सन है उसको सरकार को जरूरत क्यों महसूस हुई ? यह हमारी समझ में नहीं आता है । दूसरे इसकी स्थिति यह है कि इसके लिए पी० टी एफ ई० के 50 ग्रेड हैं, इसमें से जो इंडस्ट्रीज हैं, उनको 11 ही मिलते हैं । तो बाकी जो नहीं हैं, अगर उन उद्योगों को कोई जरूरत होगी तो क्या उसके लिए सरकार कोई व्यवस्था करने वाली है ?

SHRI J. VENGAL RAO: As the hon. Member mentioned, this project was established at Hyderabad in collaboration with Andhra Pradesh Development Corporation. The installed capacity is 500 tonnes but we are producing only 30 tonnes per month. As the hon, Member mentioned the international price is lower than indigenous price and that is why they are not in a position lo sell even these 30 tonnes. I think the duty is low and we are in correspondence with the imported material. We are not going to ban it, import.

डा० जाधव काजदाले : अभी आपने कहा कि यह सिर्फ 30 टन प्रोडक्शन करता है । आप जानते हैं कि 200 टन की जरूरत है, इसका मतलब यह है कि आज जो भी प्रोडक्शन हम देश में करते हैं इसमें से 170 टन को देश में जरूरत है जो आप प्रोडयूस नहीं करते हैं । आप जानते हैं कि रक्षा मंत्रालय हो, न्यूक्लिअर रिसर्च हो या अन्य कई चीजें हैं जहां इसकी जरूरत है । तो रिस्ट्रक्शन करने से यहां उधर एक तरफ उसके भी दाम बढ़ते रहेंगे । और दूसरी तरफ यहां के जो इंडीजिनस प्रोडक्शन है, उसके भी दाम बढ़ते रहेंगे इसलिए जब तक इसका कंपेटीटर आए नहीं बढ़ाते क्या तब तक आप ऐसी व्यवस्था की जरूरत नहीं समझते ? महोदय, मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं हमारे यहां एक सिलेंप की फैक्ट्री है । यह सिलेंप के लिए जो पी० टी० एफ ई. लगता है, वह यहां हैदराबाद में तैयार नहीं होता है । इसलिए मेहरबानी कर के इम्पोर्ट की कास्ट कम करें और जब तक यहां 200 टन नहीं बनता तब तक इन उद्योगों को पी० टी० एफ० ई० मिलता रहे, इसके लिए आप क्या व्यवस्था करने वाले हैं ?

SHRI J. VENGAL RAO: I answered this question. Hyderabad unit came under production only at the end of 1987; it has not yet reached the maximum production capacity; it is producing only 30 tonnes per month, and the price is high compared to imported material. Now, we are requesting the Finance Ministry to increase the duty. *{Interruptions)*

THE DEPUTY CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Re-opening of Bombay Unit of Union Carbide

*342. SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government arc aware that the Bombay unit of Union Carbide has been closed down by the Company for the last several months; and

(b) if so, what steps have been taken by Government to reopen this unit?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI J. VENGAL RAO) (a) Yes, Sir.

(b) Certain proopsals/suggestions have been received from the Maharashtra Government and Workers' Union in this regard. The various implications of the proposals are under study.

Sick Industrial Units in West Bengal

@*344. SHRIMATI KANAK MUKHERIEE: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) what is the number of sick industrial units in the large-scale sector in West Bengal at present;

(b) what are the reasons for their sickness;

©Previously Starred Question144, transferred from the 5th August, 1988.